भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4260

जिसका उत्तर 11 अगस्त, 2016 को दिया जाना है

जनजातीय समुदायों का विस्थापन

4260. श्री दुष्यंत चौटालाः
श्रीमती मौसम नूर **:**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल या अन्य किसी गैर–सरकारी संगठन ने हाल में देश के विभिन्न राज्यों में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जनजातीय समुदायों के विस्थापन के कारण मुख्य रूप से मानवाधिकार उल्लंघन के पैटर्न को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट हाल में जारी की है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के कितने मामले दर्ज किए गए तथा कोयले के खनन हेतु भूमि अधिग्रहण के चलते कितने जनजातीय लोग राज्य–वार विस्थापित किए गए;

(ग) क्या जनजातीय लोगों ने ओडिशा तथा छत्तीसगढ में कोयला खनन के विस्तार पर विरोध प्रकट किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) जनजातीय लोगों के हितों को संरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला,विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।